



प्रगति पथ पर गतिमान राजस्थान



शहरी विकास को नई रफ्तार - आधुनिक राजस्थान की नई पहचान

मजबूत सड़कें • सुगम यातायात • बेहतर ड्रेनेज • आधुनिक सीवरेंज • सुरक्षित सबवे • बेहतर मेडिकल सुविधाएं • श्रमिक कल्याण • स्वच्छ एवं हरित परिवहन

राजस्थान के शहरों को मिल रही ₹2,340 करोड़ की सौगातें 941 कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के
1 लाख 32 हजार 421 लाभार्थियों को ₹154 करोड़ से अधिक की सहायता राशि की डीबीटी

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में जयपुर को बड़ी सौगात

लोकार्पण

RUHS जयपुर : 128-स्लाइस CT स्कैन मशीन

जनाना चिकित्सालय, चांदपोल : नवीन आईपीडी टावर

SMS अस्पताल :

आयुष्मान टावर अंतर्गत कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज संस्थान

RUHS जयपुर :

1.5 टेस्ला MRI मशीन तथा नवीन स्नातक छात्रावास

जयपुर जिले में झोटवाड़ा के अभयपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं दूदू विधानसभा क्षेत्र के उप स्वा. केन्द्र, रेहलाना का निर्माण कार्य

शिलान्यास

जयपुर जिले के झोटवाड़ा में सैटेलाइट चिकित्सालय

पीएम ई-बस योजना

71 ई-बसों का शुभारंभ

जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों का जयपुर से
तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर से 47 ई-बसों का वर्चुअल शुभारंभ

ARBIT



The CIA Officer Who Hid 303 Gold Bars

CIA hired him because it believed the Navy had already verified his background, while the Navy assumed the CIA would conduct its own checks

Know Terms Like Cutwork, Needle, and Jacquard Jamdani

Ancient Egyptian Priests Shaved...

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

वंदे मातरम् का गायन राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक मुद्दा बनता जा रहा है

भाजपा इस बात को बड़े ध्यान से देख रही है कि कानून पास होने के बाद किसी भी स्तर पर वंदे मातरम् की अवहेलना तो नहीं हो रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता क्या अमित शाह हताश है या उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ रुक जाना चाहिए? या फिर वे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके अपना खोया हुआ राजनीतिक प्रभाव वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कहानी 1897 से शुरू होती है, जब कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम् बिना किसी झिझक या समस्या के गाया गया था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। 1930 के दशक में, जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया था, तब कुछ नेताओं ने वंदे मातरम् के तीसरे अंश पर आपत्ति जतानी शुरू की। इस अंतरे में मूर्ति पूजा का वर्णन था, जिसे इस्लाम धर्म में मान्यता नहीं है। इस विवाद को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। उन्होंने पूरे विवाद का

- कांग्रेस ने भी मान लिया है, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है, कि कानून बनने के बाद वंदे मातरम् को पूरा गाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, फिर भी थोड़ी बेचैनी सी है।
- सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम् चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की सहानुभूति पाना चाहती है, वहीं भाजपा इस मुद्दे पर हिंदू वोटों का धुवीकरण करना चाहती है और वंदे मातरम् के संदर्भ में विपक्षी दलों की मामूली सी चूक को भी हवा दे रही है।
- इसी संदर्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर वंदे मातरम् के गायन में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और माफ़ी मांगने को कहा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस से जाँच करने और रिपोर्ट देने को भी कहा है।

विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस

तीसरे अंतरे को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि जब भारत स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है, तब सभी विवादाल्पद मुद्दों को अलग रख देना चाहिए। टैगोर ने बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय से भी बात की। बंकिम चन्द्र ने कहा कि उन्हें किसी भी अंतरे को हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद मामला सुलझा लिया

गया और विवाद समाप्त हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया कि मुसलमानों को लगातार उकसाते रहना जरूरी है, ताकि हिंदू-मुस्लिम विभाजन पहले से कहीं अधिक गहरा हो सके। मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया। 15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में यह सातवीं सर्वदलीय बैठक है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचैतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचैतक प्रतिपक्ष रफीक खान सहित, विभिन्न दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। देवनानी ने कहा कि विधानसभा जनहित के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच है। सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित, सभी विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों के बीच संवाद, समन्वय और विश्वास का वातावरण तैयार होता है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में जनमहत्व के विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण जरूरी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित, गरिमापूर्ण और जनहित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नितिन नबीन की टीम में राज्य के पाँच नेता, सतीश पूनिया राष्ट्रीय महामंत्री बने

वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष, सुनील बंसल महामंत्री, राजेश मंगल सह कोषाध्यक्ष व मन्जालाल रावत एसटी मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त

जयपुर, 17 अगस्ता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में राजस्थान को मिला मजबूत प्रतिनिधित्व प्रदेश भाजपा की राजनीति के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, उदयपुर सांसद मन्जालाल रावत को एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। एक ही प्रदेश से कई नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिलना भाजपा की संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाना नई टीम में राजस्थान के लिहाज से सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 2019 से 2023 तक राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूनिया

- भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधामोहन लाल अग्रवाल तथा राष्ट्रीय सचिव सांसद अलका गुर्जर को स्थान नहीं मिला।

संगठन में लंबे अनुभव के साथ सक्रिय रहे हैं। जून 2026 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से उनका राजनीतिक दायरा प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। पूनिया को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आने वाले समय में चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और पार्टी के महत्वपूर्ण अभियानों में उनकी भूमिका बढ़ सकती है। दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखना उनके राजनीतिक अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका को

लेकर पार्टी के भरोसे का संकेत माना जा रहा है। राजे इससे पहले जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में भी उपाध्यक्ष थीं। उदयपुर सांसद मन्जालाल रावत को भाजपा एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान सहित, आदिवासी बहुल राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में रावत की भूमिका अहम हो सकती है। राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को पीपूष गोयल के साथ राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इन नियुक्तियों के जरिए राजस्थान के संगठनात्मक अनुभव वाले नेताओं को केन्द्रीय संगठन में जगह दी गई है। नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल को स्थान नहीं मिला है। राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर भी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना सकीं। इसके बजाय राजेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या देवेन्द्र फड़नवीस दिल्ली शिफ्ट होंगे?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की प्र.मंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर राजनैतिक हलकों में यह सवाल पूछा जा रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के सोमवार को नई दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी मुलाकात ने एक बार फिर उन्हें केंद्र सरकार में लिए जाने की संभावना को लेकर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। फडणवीस ने प्रधानमंत्री को राज्य की प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इनमें राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो विस्तार और नदी जोड़ो परियोजनाएँ शामिल हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य की संयुक्त योजनाओं के लिए केंद्र से और अधिक सहयोग की भी मांग की। हालांकि, बाद में उन्होंने दिल्ली

- फड़नवीस का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकाल का प्रशासनिक अनुभव है, वे युवा हैं और उनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है, यही नहीं, अक्सर प्रधानमंत्री के पद पर मोदी के विकल्प के रूप में उनका नाम लिया जाता है, हालांकि, खुद फड़नवीस इससे इंकार कर चुके हैं।
- चर्चा है कि अगर फड़नवीस केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उन्हें संभवतया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है।
- फड़नवीस ने कहा कि उनकी प्र.मंत्री मोदी से मुलाकात राज्य की योजनाओं के संदर्भ में थी, वे दिल्ली शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और महाराष्ट्र में ही बने रहेंगे।

आने की अटकलों को खारिज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में फड़नवीस ने कहा कि जो लोग ऐसी अटकलों के “गुब्बारे” या “पतंगें” उड़ा रहे हैं, वे

ऐसा करते रहें, लेकिन वे महाराष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। फड़नवीस को लेकर मौजूदा अटकलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कतर में रहने वाले भारतीय यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे

नई दिल्ली, 17 अगस्ता कतर में रहने वाले भारतीय अब डाकघरों के माध्यम से भारत में यूपीआई से जुड़े बैंक खातों में सीधे पैसे भेज सकेंगे। कतर-भारत धन प्रेषण (पोस्टल रেমिटेंस)

- यह सेवा डाक विभाग तथा कतर डाक सहित संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है।

सेवा 15 अगस्त से शुरू हो गई है। यह सुविधा डाक विभाग और कतर डाक सहित, अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है। केन्द्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि इस सेवा के तहत कतर में ग्राहक कतर के डाकघर जाकर भारत में किसी व्यक्ति की यूपीआई आईडी के जरिए पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“दिमागी नक्सल” कौन होता है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्र.मंत्री मोदी की “दिमागी नक्सल” टिप्पणी ने नई राजनैतिक बहस छेड़ दी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सरकार के विरोधियों के लिए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कई अन्य बातों के अलावा, भाजपा सरकार के रवैये में युवाओं के प्रति विरोधाभास को भी दर्शाता है। एक ओर मोदी ने मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, एआई कौशल प्रशिक्षण और नशामुक्त भारत जैसी घोषणाओं के जरिए युवाओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सरकार को महत्वाकांक्षी युवा भारतीयों के साथ खड़े साझेदार के रूप में पेश किया। दूसरी ओर, उन्होंने संकेत दिया कि इसी युवा वर्ग के एक भाग को दिमागी नक्सलियों द्वारा गुमराह करने या ब्रेनवॉश किए जाने का खतरा है और उसे मुख्यधारा में वापस लाने की जरूरत है। इसका निहित संदेश साफ है: छात्रों की वास्तविक आकांक्षाओं का स्वागत

- प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कई योजनाएँ घोषित कीं, साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के एक वर्ग का “दिमागी नक्सली” लोगों द्वारा “ब्रेन वॉश” किया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है।

- विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्र.मंत्री का इशारा स्वतंत्र विचारधारा और वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठनों की ओर है और उनकी दिमागी नक्सल टिप्पणी सरकार की भावी दिशा का संकेत दे रही है।

है, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाली या स्वतंत्र विचारधारा की छात्र राजनीति शक की नजर से देखी जाती है। “दिमागी नक्सल” का तंज इस बात का संकेत भी है कि आने वाले महीनों में छात्र राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। सभी संकेतों से लगता है कि एबीवीपी के लिए यह काफी सक्रिय दौर होने वाला है। परिसरों में अपनी पहुंच बढ़ाने, जवाबी लामबंदी करने और अपने विरोधियों को राष्-

त्रोधी या वैचारिक रूप से दृष्टित बताकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश तेज हो सकती है। एबीवीपी खुद को युवा विकास की वैध आवाज के रूप में पेश करती रहेगी, जबकि वामपंथी रुझान वाले या स्वतंत्र छात्र संगठनों को बदनाम करने के लिए दिमागी नक्सल जैसा नया शब्द उस इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अनुकूल रख रखने वाले युवाओं के लिए प्रोत्साहन और असहमति जताने वालों के लिए सख्ती

की यह दोहरी रणनीति सीजेपी के बाद की जैनरेशन जी की उभरती मुखरता को नियंत्रित कर पाएगी या नहीं, यह अभी एक खुला राजनीतिक सवाल है। कॉकरोच जनता पार्टी के जैनरेशन ज़ैड आंदोलन, जिसने पेपर लोक के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, उससे जुड़े छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री के भाषण को इस बात के एक और प्रमाण के रूप में लिया है कि सरकार युवाओं के गुस्से को समझने और उसके मूल कारणों को दूर करने के बजाय उसे किसी लेबल से जोड़ने में अधिक सहज है। सीजेपी और वामपंथी छात्र संगठनों को पहले ही अर्बन नक्सल जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा है। अब इस्तेमाल किया गया नया शब्द उस रणनीति के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसे ऐसी पीढ़ी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अगर एयरलाइन किराया बढ़ाये तो केन्द्र उड़ानें रोकें’

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। उच्चतम न्यायालय ने त्योंहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर एयरलाइंस कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उनकी उड़ानें रोकने तक के कदमों पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की

- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को सख्त निर्देश दिये।

अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यात्रियों के हित में व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन उसके पालन और नियमन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि हवाई किराये से जुड़े नये नियम बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार ने नियमों का डाफ्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा। केंद्र सरकार ने कहा कि तीन हफ्ते में नये नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इलायची और माउथ फ्रैशनर के बहाने पान मसाला ब्रांड का प्रचार, कानून से खिलवाड़ की एक और मिसाल

महाराष्ट्र सरकार ने विमल इलायची के प्रचार के लिए बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरूख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ एक्शन लेकर “सरोगेट एडवर्टिज़मेंट” के खेल को सुर्खियों में ला दिया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता। विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई ने भारत की सरोगेट विज्ञापन (छद्म विज्ञापन) को फिर से चर्चा में ला दिया है। यह विवाद एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: किसी ऐसे उत्पाद का विज्ञापन, जो देखने में पूरी तरह वैध है, कब प्रतिबंधित तंबाकू या पान मसाला उत्पाद का अप्रत्यक्ष विज्ञापन बन जाता है?

- “सरोगेट” यानि छद्म विज्ञापन वे विज्ञापन हैं, जिनमें किसी प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार करने के लिए किसी अन्य प्रोडक्ट का सहारा लिया जाता है, जैसे विमल गुटखा के प्रचार के लिए विमल इलायची का विज्ञापन किया जाता है।
- भारत में तंबाकू आधारित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून रोक है और इस कानून में बाद में ऐसे नियम भी जोड़ दिए गए, जिनमें तंबाकू उत्पाद ब्रांड के प्रचार के लिए अन्य उत्पाद का प्रचार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- उपभोक्ता संरक्षण कानून की गाइडलाइन्स में भी “सरोगेट” विज्ञापन पर रोक लगाई गई है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्मी हस्तियों पर की गई कार्यवाही सैलिब्रिटी विवाद बन कर न रह जाए, यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि, यह मुद्दा इस विवाद का समाधान कर सकता है कि क्या किसी वैध उत्पाद की आड़ में प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार किया जा सकता है।

वाली कंपनियाँ इलायची, माउथ फ्रेशनर और अन्य उत्पादों जैसे ब्रांड एक्सटेंशन के जरिए, अपने ब्रांड को लोगों की नजर में बनाए रखती हैं,

जबकि उक्त उत्पादों के सीधे विज्ञापन पर प्रतिबंध है। भारत में इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए पहले से ही एक

मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सी.ओ.पी.टी.ए.), 2003 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।

इस कानून के तहत बाद में बनाए गए नियम अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर भी रोक लगाते हैं। इनमें तम्बाकू उत्पाद के नाम या ब्रांड का इस्तेमाल अन्य सामान

सेवाओं या कार्यक्रमों के प्रचार के लिए करना भी शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण कानून की व्यवस्था भी इसमें एक और स्तर जोड़ती है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की 2022 की गाइडलाइंस उन वस्तुओं और सेवाओं के सरोगेट या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाती हैं, जिनके विज्ञापन पर पहले से प्रतिबंध था रोक है। फिर भी इन नियमों को लागू करना मुश्किल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का बचाव (डिफेंस) सीधा है: विज्ञापन पूरी तरह से वैध उत्पाद के लिए है। इस बचाव की अदालतों में परीक्षा हो चुकी है। विमल इलायची से जुड़े एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- उन्होंने भाजपा व शीर्ष नेतृत्व को मार्ग दर्शन व सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया।

कर लिया जाए। इससे पहले भी उन्होंने 30 जुलाई को इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। सोमवार को भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भेजा है और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

⊕

⊕

⊕

⊕

CMYK



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

जल प्रबंधन में नए कीर्तिमान जल समृद्ध हो रहा राजस्थान

₹91,000 करोड़ की लागत से राम जल सेतु लिंक परियोजना

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- 4.98 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा
- 17 जिलों को पेयजल-
जयपुर, अलवर,
दौसा, भरतपुर,
सवाई माधोपुर,
करौली, टोंक,
बूंदी, कोटा, बारां,
झालावाड़, अजमेर,
ब्यावर, डीग
कोटपूतली-बहरोड़,
खैरथल-तिजारा,
धौलपुर



₹34,102 करोड़ की यमुना जल परियोजना

शेखावाटी को वर्षों बाद जल

32 वर्षों का इंतजार पूरा

चूरु, सीकर, झुंझुनू – भरपूर पानी



राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर

गंग, भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहरी-तंत्र के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण के लिए राशि ₹5500 करोड़

लाभान्वित जिले - हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरु, बीकानेर, फलौदी

जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, डीडवाना- कुचामन, बाड़मेर और बालोतरा

ब्राह्मणी-राणा प्रताप सागर- बनास लिंक

680 एमसीएम जल बनास नदी में अपवर्तन
लाभान्वित जिले भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा,
सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर एवं डीग

₹2,500 करोड़

की अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना
से बांसवाड़ा के 338 गांवों में सिंचाई

देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांध का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले में जल उपलब्धता सुनिश्चित
करने हेतु खारी फीडर की जल संवहन क्षमता को दोगुना
करने की लगभग ₹150 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना

₹7,355 करोड़ की

परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से कोटा, बारां, झालावाड़ के
571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सिंचाई एवं 1402 गांवों में पेयजल सुविधा

पाली एवं सिरौही में पेयजल आपूर्ति हेतु सेई एवं साबरमती बांधों का निर्माण
कर जवाई बांध में पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना लागत ₹1,255.90 करोड़ है
साथ ही, सेई बांध की टनल क्षमता बढ़ाने पर ₹65 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

माही बेसिन के अनास एवं सोम नदियों के 500 MCM अधिशेष जल को जाखम बांध, जयसमंद बांध के साथ साथ सोम-कमला-अंबा बांध के
माध्यम से जवाई बांध एवं जालौर तक आपवर्तित करने का संकल्प
लाभान्वित जिले: बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूबर, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालौर एवं जोधपुर

#PURITY BEFORE PRAYER

Ancient Egyptian
Priests Shaved Every
Hair from Their Bodies

More than three thousand years before the rise of modern public health, Egyptian temple culture had embedded regular washing, clean clothing, careful grooming



To serve in the temples of ancient Egypt demanded far more than religious devotion. It required a level of physical cleanliness so rigorous that it governed every aspect of a priest's daily life. Before entering the sacred precincts, priests were expected to present themselves in a state of complete ritual purity, a standard that included shaving every hair from their bodies.

The head, beard, eyebrows, and even body hair were removed. Ancient sources indicate that temple priests shaved themselves regularly, often every three days, ensuring that not a single hair remained. This was not a matter of appearance or fashion; it was a religious obligation. To stand before the gods, one had to be free from anything considered impure.

To the Egyptians, hair could trap sweat, dirt, and parasites such as lice. By removing it completely, priests minimized the risk of contamination before performing sacred rituals. Their concern with cleanliness extended far beyond shaving. They bathed several times each day, traditionally described as four times, twice during the day and twice at night, to maintain ritual purity. They also chewed aromatic plants or herbs to keep their breath fresh before reciting prayers and offering sacrifices.

Their clothing reflected the same philosophy. Priests wore freshly laundered white linen garments, a fabric associated with purity and cleanliness. Animal wool, by contrast, was generally prohibited within temple rituals because it was regarded as ritually impure. Every detail, from clothing to personal grooming, reinforced the belief that the divine deserved absolute cleanliness. Their dietary rules were equally strict. Many priests abstained from foods such as fish and beans during periods of temple service, although these restrictions could vary depending on the deity and the temple in which they served. Contact with animals considered ritually unclean, particularly pigs, required

purification before a priest could once again enter sacred space. To modern eyes, these practices may appear to be purely religious customs. Yet, many of them had practical consequences. Frequent bathing reduced the accumulation of dirt and parasites. Regular shaving helped control lice and other insects. Clean linen garments were cooler and more hygienic in Egypt's hot climate. Although the Egyptians explained these practices through the language of ritual rather than medicine, many of them also promoted better personal hygiene.

It would, however, be an oversimplification to claim that the Egyptians had discovered modern germ theory or that medieval Europeans simply "refused to bathe." Medieval Europe did experience devastating epidemics such as the Black Death, but the causes were far more complex, involving bacteria transmitted primarily through fleas carried by rodents, along with crowded living conditions and limited medical knowledge. Europeans did bathe, though bathing customs varied widely over time and place and generally did not match the ritual standards observed in Egyptian temples.

Nevertheless, the contrast is striking. More than three thousand years before the rise of modern public health, Egyptian temple culture had embedded regular washing, clean clothing, careful grooming, and dietary discipline into daily religious practice. What they called ritual purity often produced tangible hygienic benefits.

The priests of ancient Egypt were not merely performing ceremonies; they were living according to one of history's most exacting codes of cleanliness. Their shaved heads, spotless linen, frequent ablutions, and strict rules of conduct reflected a civilization that saw purity as the bridge between humanity and the divine. Whether understood as religion or hygiene, their practices demonstrate a remarkable awareness that cleanliness was essential, not only for worship, but for life itself.

The CIA
Officer
Who
Hid 303
Gold Bars

● Verna Mohon

Imagine discovering 303 gold bars, each weighing one kilogram, stacked inside the home of a senior intelligence officer. At current prices, each bar is worth roughly US\$130,000, making the cache worth close to US\$40 million. It sounds like the plot of a spy thriller. Instead, it is the basis of a federal criminal case involving David J. Rush, a former senior officer of the U.S. Central Intelligence Agency (CIA).

The CIA officer was arrested for possessing several hundred gold bars stashed in his house, received additional money or valuables as part of his work for the agency, which federal investigators have not been able to locate, four people with knowledge of the investigation say.

The officer, David Rush, requested the money or other valuables to provide the resources to agency sources abroad, the sources say. It is unclear if the money or valuables were used for their intended purposes.

CIA officers typically provide money or other compensation to foreign contacts who spy for the agency. But the agency requires officers to follow an approval process and be able to fully account for all money or other valuables, former intelligence officers say.

The irony is difficult to ignore. The CIA is tasked with monitoring some of the world's most sensitive security threats, from tracking North Korea's weapons programmes and monitoring Iran's nuclear facilities to running sophisticated intel-

ligence and surveillance networks across the globe. Yet, according to federal prosecutors, the agency failed to detect the alleged diversion of tens of millions of dollars in gold entrusted to one of its own senior officials.

On 19 May 2026, FBI agents arrested David J. Rush at his residence in Ashburn, Virginia. Rush had held a Senior Executive Service (SES) position within the CIA and possessed a Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS//SCI) security clearance, granting him access to some of the most closely guarded intelligence in the United States. According to the indictment, however, the same individual allegedly spent decades constructing an elaborate web of deception that ultimately culminated in one of the most remarkable fraud cases to emerge from the American intelligence community.

According to prosecutors, the story began in 1997, when Rush enlisted in the U.S. Navy Reserve. To become a commissioned officer, a college degree was required. Investigators allege that Rush did not possess one and instead fabricated academic credentials, including a counterfeit degree purportedly issued by a university in South Carolina. He was commissioned as an ensign despite the alleged falsified qualifications.

The deception allegedly expanded over the following years. Although Rush worked as an Information Systems Technician, prosecutors say he falsely represented himself as a naval aviator and even claimed credentials from the prestigious U.S. Naval Test Pilot School. He reportedly applied to join the CIA three times. On his third



David J. Rush is a former CIA agent who allegedly created a fake intelligence program to siphon resources from the CIA.

#DAVID J. RUSH CASE



Former CIA Officer David Rush in court.

attempt, he succeeded, allegedly using the same fabricated educational and professional credentials. One of the most striking aspects of the case is the apparent failure of institutional verification. During the FBI investigation, officials contacted the universities and organizations whose credentials Rush had claimed. According to court filings, they confirmed that he had never attended the institutions in question. Yet, investigators allege that the CIA hired him because it believed the Navy had already verified his background, while the Navy assumed the CIA would conduct its own checks. This chain of assumptions, rather than independent verification, allegedly allowed fabricated credentials to survive repeated scrutiny.

Once inside the agency, Rush built a successful career. He rose through the ranks, received promotions, and earned increased compensation. Holding one of the government's highest security clearances, he was entrusted with responsibilities involving highly

sensitive intelligence operations. He wasn't just highly intelligent. He was also capable, calm under pressure and a physical specimen, according to interviews with a half-dozen former Ashburn volunteer firefighters.

"The David Rush, I remember, he was chiseled," said Jeff Bellmer, a retired lieutenant at the department. "Big back, skinny waist, fit." Despite his intellectual and physical gifts, Rush didn't act like a big shot, his former fire department colleagues said. He was reserved and humble. But when he did get to talking about his military career, the stories he told were just amazing, how he had graduated first in his class at Top Gun, the legendary Navy fighter pilot school, and flown F-14 Tomcat fighter jets over Iraq and Afghanistan.

"Rush told me he had ejected and bailed out of two F-14s, and the third one he landed over there at Andrews with the cockpit on fire," Bellmer said.

"He was just such a neat guy for me at the time," Bellmer added. "The

"The David Rush, I remember, he was chiseled," said Jeff Bellmer, a retired lieutenant at the department. "Big back, skinny waist, fit." Despite his intellectual and physical gifts, Rush didn't act like a big shot, his former fire department colleagues said. He was reserved and humble. But when he did get to talking about his military career, the stories he told were just amazing, how he had graduated first in his class at Top Gun, the legendary Navy fighter pilot school, and flown F-14 Tomcat fighter jets over Iraq and Afghanistan." Rush told me he had ejected and bailed out of two F-14s, and the third one he landed over there at Andrews with the cockpit on fire," Bellmer said.



obtained additional quantities of gold and foreign currency. When agency officials later attempted to account for the assets, they reportedly discovered significant discrepancies. CIA Director John Ratcliffe referred the matter to the FBI after potential legal violations were identified.

In May 2026, FBI agents executed a search warrant at Rush's Virginia residence. According to court documents, they recovered 303 one-kilogram gold bars, valued at approximately US\$40 million, along with luxury watches and other high-value assets. Rush was arrested the following morning.

Federal prosecutors argued that the magnitude of the alleged fraud and the resources available to the defendant created a substantial flight risk. A federal judge denied bail, ordering Rush to remain in federal custody while the case proceeds. At the time of writing, Rush has not entered a guilty plea, and the allegations remain subject to judicial determination.

Investigators also uncovered another alleged layer of deception. Although Rush was reportedly honorably discharged from the U.S. Navy in 2015 with the rank of lieutenant, prosecutors allege that he continued telling the CIA he remained on active military service until September 2025. During that period, he allegedly received approximately US\$77,000 in paid military leave benefits from the agency, giving rise to additional criminal allegations.

The case raises an important question: How could someone allegedly maintain such deception for nearly three decades? Security experts often describe this phe-

first real naval aviator that I had come across."

Rush made a similar impression on Lloyd Harting, another former Ashburn volunteer firefighter. "He told me he was a former fighter pilot, and I had no reason to doubt him," Harting said. "He was completely believable. He looked the part. He talked the part."

The alleged fraud took a dramatic turn in November 2025. According to federal prosecutors, Rush requested physical gold bars and foreign currency from the CIA, claiming they were required for operational expenses associated with covert missions. Such requests were not inherently unusual. Intelligence agencies sometimes use gold and foreign currencies because they can be transported discreetly, function outside conventional banking systems, and support clandestine operations where digital transactions would be impractical or traceable.

Between November 2025 and March 2026, prosecutors allege that Rush repeatedly requested and

monon as institutional assumption transfer. In complex bureaucracies, organizations sometimes assume that another agency has already completed critical verification. When responsibility becomes fragmented, accountability can disappear into procedural gaps. Rather than repeatedly confirming credentials, each institution relies on previous checks that may never have occurred. If forged documents are convincing enough, or if verification is incomplete, the deception can persist for years.

Whether the failures resulted from inadequate background investigations, misplaced institutional trust, or exceptionally sophisticated document fabrication will likely remain central issues as the case unfolds.

Beyond the individual allegations, the Rush case raises broader questions about oversight within government institutions. Intelligence agencies are entrusted with enormous authority, extensive financial resources, and access to classified information because they operate in the interest of national security. Public confidence depends not only on their operational effectiveness abroad but also on the strength of their internal accountability.

Ultimately, the alleged loss was not merely the disappearance of gold bars. The resources involved were public assets funded by taxpayers. The case illustrates that even organizations built to monitor global threats can themselves become vulnerable when verification systems fail.

rajeshsharma1049@gmail.com



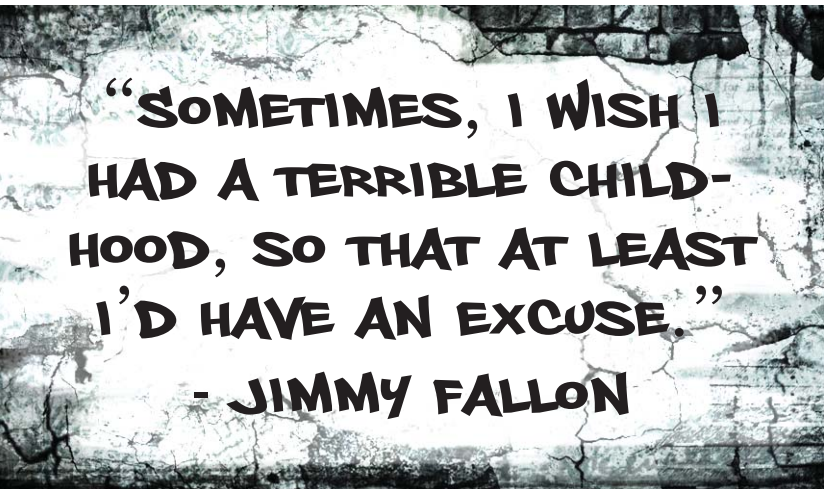
By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

THE WALL



BABY BLUES

